the rejected claims, as I am very confident that a majority of them are genuine. Thank you, Sir.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI K. K. RAGESH (Kerala): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

**श्री रवि प्रकाश वर्मा** (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

MR. CHAIRMAN: All these raising their hands have to write their names on a slip and send it to the Table. It is not possible for officials sitting on the Table to see all the Members who are associating and note their names simultaneously.

**Need to protect Kanwar Lake Bird Sanctuary in Begusarai, Bihar**

**श्री राकेश सिन्हा** (नाम निर्देशित): सभापति महोदय, मैं एक ऐसे विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो यह दिखाता है कि किस प्रकार से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों और पर्यटक स्थलों को खोते जा रहे हैं। बिहार के बेगूसराय के मंझौल में लगभग 5,467 हैक्टेयर जमीन पर एक झील है, जिसे कांवर झील कहते हैं। इसे बाद में बिहार सरकार की अधिसूचना में 6,311 हैक्टेयर किया गया है, जो अपने आप में एशिया की सबसे बड़ी झील है। उसका पानी इतना अच्छा होता था कि उस झील को देखने के लिए और उसका पानी पीने के लिए लाखों लोग वहां आते थे। उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि नवम्बर से लेकर मार्च तक साइबेरिया के लाखों अनगिनत रंग-बिरंगे पक्षी वहां आते थे, जोकि इस पर्यटक स्थल को और अधिक आकर्षण का केंद्र बना देते थे। आज वह झील सूख रही है और प्राय: सूख चुकी है। उस पर किसी भी सरकार की नज़र नहीं गई है।

[श्री राकेश सिन्हा]

मैं सरकार और मंत्रालय से यह अपेक्षा रखता हूं कि उस झील को रिवाइव किया जाए और हमारे लाखों अतिथि, जो साइबेरिया से आते थे, हम उन्हें पुन: भारत में बुलाएं। वे अतिथि जिनका एक अलग रूप होता था, वे रंग-बिरंगे पक्षी इस प्रकार का सौंदर्य देते थे और ऐसा लगता था कि जैसे भारत उनका सेकेन्ड होम हो।

मैं यह उम्मीद करता हूं कि पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और बिहार सरकार, तीनों मिलकर उस झील को अविलम्ब रिवाइव करेंगे, जिससे हमारा वह पर्यटक स्थल बचा रहे और यह धरोहर जो कि 700 साल पुरानी है, वह वर्तमान में रहे, भविष्य में भी बनी रहे और पीढ़ियों के लिए वह एक याद के रूप में नहीं बल्कि वर्तमान के रूप में रहे।

**श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव** (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

**डा. सी.पी. ठाकुर** (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

**Need to withhold legislation on dam safety**

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Hon. Chairman, Sir, the Central Government is now proposing to introduce the Dam Safety Bill, 2019.

I would like to draw the kind attention of the Central Government to a unanimous resolution passed by the Legislative Assembly of Tamil Nadu on 26th June, 2018. I may be permitted to quote the resolution. It says:

> "As the proposed draft Dam Safety Bill contain Clauses which violate the rights of Tamil Nadu, especially with respect to dams constructed by the Government of Tamil Nadu in the neighbouring State and would cause various problems in their maintenance and operation, this House urges the Central Government to take up the legislation on dam safety only after consulting the States and after arriving at consensus and till then keep in abeyance the process of legislating on dam safety."

Sir, there are four dams of Tamil Nadu located in Kerala, namely Mullaiperiyar, Parambikulam, Thunakadavu and Peruvaripallam. These are now under the safe custody of the Government of Tamil Nadu. They are maintained by the Government of Tamil Nadu. Now, the State of Tamil Nadu has the existing rights to maintain these dams. Sir, now, the proposed Dam Safety Bill is taking away these rights. It is unfair. It is unconstitutional. It is illegal and it would cause a great loss to us.